CONTENTS

Fifteenth Series, Vol.XX, Ninth Session, 2011/1933 (Saka) No.4, Friday, November 25, 2011/ Agrahayana 4, 1933(Saka)

SUBJECT	PAGES
REFERENCE BY THE SPEAKER	
Condemning the unfortunate incident of assult on Shri Sharad Pawar, the Minister of Agriculture and Minister of Food Processing Industries	2
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.61 to 80	4-93
Unstarred Question Nos.691 to 920	94-613

^{*} Due to continuous interruptions in the House, Starred questions could not be taken up for oral answers. Therefore, these starred questions were treated as unstarred questions.

SUBMISSION BY MEMBERS Re:Unfortunate incident of assault on the Minister of Agriculture and Minister of Food Processing Industries	614-628
and Minister of Food Processing Industries during a function in New Delhi on 24.11.11	
PAPERS LAID ON THE TABLE	629-631
ELECTION TO COMMITTEE	632
Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	
STATEMENTS BY MINISTERS	
(i) First meeting of Prime Minister's Committee on National e- Governance Plan (NEGP) held on 23.11.11 Shri Kapil Sibal	633-634
(ii) (a)Decision of Union Cabinet on the Revival Reform and Restructuring package for handloom sector	635-637
(ii) (b)Policy on Foreign Direct Investment for allowing FDI in Multi- Brand Retail Trading and Liberalization of the policy in Single Brand Retail Trading	
Shri Anand Sharma	638-640
BUSINESS OF THE HOUSE	641
MOTION RE: THIRTIETH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	642
DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS- (GENERAL), 2011-2012	643
ANNEXURE – I	
Member-wise Index to Starred Questions	644
Member-wise Index to Unstarred Questions	645-649
ANNEXURE – II	
Ministry-wise Index to Starred Questions	650
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	651

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia
Shri P.C. Chacko
Shrimati Sumitra Mahajan
Shri Inder Singh Namdhari
Shri Francisco Cosme Sardinha
Shri Arjun Charan Sethi
Dr. Raghuvansh Prasad Singh
Dr. M. Thambidurai
Dr. Girija Vyas
Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, November 25, 2011/ Agrahayana 4, 1933(Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

REFERENCE BY THE SPEAKER

Condemning the unfortunate incident of assult on Shri Sharad Pawar, the Minister of Agriculture and Minister of Food Processing Industries

MADAM SPEAKER: Hon. Members, the House strongly condemns the unfortunate incident of assault on Shri Sharad Pawar, hon. Union Minister of Agriculture and Minister of Food Processing Industries during a function in New Delhi on 24th November, 2011 and expresses its unequivocal disapproval of taking recourse to violent and undemocratic means to express disagreement.

... (Interruptions)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): इसमें एक निंदा प्रस्ताव जाना चाहिए। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Now, let us take up Question Hour. Q. 61.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please take your seat. Please take your seat. Please sit down. Please take your seat. Please take your seat. Please take your seat. Please take your seat.

... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया इन कागजों को नीचे रखिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12.00 noon.

11.03 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

12.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Dr. M. Thambidurai in the Chair)

MR. CHAIRMAN: Now, Papers to be laid on the Table of the House.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): I would request my hon. colleagues just to give me one minute.... (*Interruptions*)

12.0 ½ hrs

SUBMISSION BY MEMBERS

Re:Unfortunate incident of assault on the Minister of Agriculture and Minister of Food Processing Industries during a function in New Delhi on 24.11.11

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seat. The hon. Minister wants to make some Statement. Afterwards, we can take up Papers to be Laid, etc. SHRI PRANAB MUKHERJEE: I would request my hon. colleagues to give me just one second to speak on behalf of my colleagues to condemn the attack against one of our senior Ministers, a Parliamentarian and a politician of long-standing. We have divergences of views. People may express their views in the strongest words. There is no harm in it. But an attempt to cause harm physically and resort to violence cannot be accepted in any democratic polity. I would like all my colleagues to condemn it in the strongest terms. Thank you.

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): सभापति जी, नेता सदन ने अभी कल की घटना के बारे में जो भावनाएं प्रकट की हैं, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से उसके साथ सम्बद्ध करती हूं।

कल की इस घटना की जितनी निन्दा की जाये, उतनी कम है। मैंने तो कल संवाददाता सम्मेलन करके इसकी पुरजोर निन्दा की है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता। बहुत विषयों पर हमारे सरकार से और सरकार के मंत्रियों से मतभेद होते हैं, बहुत सी नीतियों पर हमारी असहमति होती है, लेकिन उसको कहने का एक तरीका है और वह तरीका कभी भी हिंसक नहीं हो सकता।

जहां तक शरद भाऊ का सवाल है, वे व्यक्तिगत रूप में बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं। वे इतने अनुभवी राजनेता हैं कि उन्होंने अपने शब्दों से कभी किसी को आघात नहीं पहुंचाया, कभी किसी को आहत नहीं किया। इतने शालीन व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना घटे, इसके लिए यह और ज्यादा निन्दनीय हो जाती है। इसलिए नेता सदन की भावनाओं से स्वयं को सम्बद्ध करते हुए मैं इस घटना की पुरजोर निन्दा करती हूं।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): सभापित जी, कल की जो घटना है, उसके बारे में प्रणव बाबू और सुषमा जी ने अपनी भावनाएं व्यक्त की है। यह जो शरद पवार जी के साथ घटना घटी है, इस देश में जो बड़ी मुश्किल से लोकशाही और लोकतंत्र आया है और जिस तरह से देश में सारे मामले चल रहे हैं, यह ठीक बात नहीं है। यह देश महावीर का, बुद्ध का है, इस देश को गांधी जी की अगुवाई में आजादी मिली है, अहिंसा हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रही है और उसी के जिरये हिन्दुस्तान को जो आजादी मिली है। इसी वजह से हम लोग आज यहां बैठे हैं। देश भर में लुम्पन एलीमेंट्स जिस तरह से बढ़ रहे हैं और जिस तरह से प्रचार हो रहा है, जिस तरह से पूरे देश में लोकतंत्र को चलाने की जितनी तरह की संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं की भी कहीं न कहीं इसमें हिस्सेदारी हो जाती है।

यह एक आदमी का सवाल नहीं है, कई लोगों का सवाल है। हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं, उसके पीछे एक कारण यह भी है कि पूरे देश भर में जो चौबीस घंटे लोगों की खिदमत करते हैं और हमारे बीच में जो खराब लोग होते हैं, उनके खिलाफ हम लोग जान सटाकर यहां बात करते हैं। कोई ऐसी संस्था नहीं है, कोई ऐसी जमात नहीं है, लेकिन इस देश में एक वातावरण बन रहा है, जो राजनीतिक लोग हैं, जो तीस, पैंतीस या चालीस साल से बेदाग ईमानदारी कि से के लोगों की चौबीस घंटे सेवा करते हैं। कहीं दुख हो, कहीं दर्द हो, तो राजनीतिक लोग वहाँ आपको खड़े मिलेंगे, लेकिन जिस तरीके का वातावरण बन रहा है, इस पर रोक नहीं लगी, तो मैं सोचता हूं कि हम लोगों को जो आजादी मिली है, जो दिन भर हम चिल्लाते हैं कि हमको आजादी है, हमको आजादी है, तो वह आजादी मर्यादा के साथ है। मर्यादा को तोड़कर जो आजादी है, हम उस आजादी को खत्म करेंगे। जिस तरह से कल देश में एक बड़ा फैसला एफडीआई का हो गया, लेकिन चर्चा दिन भर, चौबीस घंटे इसी की रही और एक थप्पड़ नहीं दिखाया जाता है, एक थप्पड़ के पचास थप्पड़ बनाए जाते हैं। पचास थप्पड़ बनाकर बात चलायी जाती है। कहां जा रहे हैं हम लोग? कल प्रणव बाबू ने जो कहा, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं, कहां पहुंच रहे हैं हम लोग, कहां जा रहे हैं हम लोग? हम लोग इस सदन में बैठते हैं यानी यहां से ज्यादा पारदर्शिता कहीं नहीं है। हम अपने साथियों के गुनाहों को जान सटाकर उजागर करते हैं। ये जितने लोग बंद हैं,

इसी पार्लियामेंट के पुरूषार्थ से बंद हैं। कितनी बार हम लोगों ने भ्रष्टाचार के बारे में कहा, कितनी ही बार महंगाई का सवाल उठाया, कितने जुलूस निकले, कितने जलसे निकले, आडवाणी जी की रथ यात्रा से लेकर सारे लोग, हम जिंदगी भर में कितनी बार जेल गए, कितनी बार पुलिस ने मारा और जिंदगी के इस दौर में इस तरह से अपमानित होने का काम और इस तरह का वातावरण बनना और सरकार सो रही है।...(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): सरकार कहां सो रही है? ...(व्यवधान)

श्री शरद यादव: बैठिए। ...(व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि हम और आप ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: No controversy, please.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: We are discussing a very serious issue.

... (Interruptions)

श्री शरद यादव: यह लड़ने की बात नहीं है, यह समझने की बात है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि संस्थायें और लोकतंत्र की मर्यादा की रेखायें खींची जाएं। यदि यह नहीं होंगी, तो हमारी मर्यादा हो, चाहे दूसरी संस्थाओं की मर्यादा हो, वह मर्यादा नहीं बनेगी, तो इन सारी चीजों को कोई रोक नहीं सकता है। ऐसी स्थिति है कि आदमी को जैसे लाल किले पर खड़े होकर अपमानित करना है, इसी तरह का मामला होता रहता है, इसी तरह की चीजें होती रहती हैं। ये चीजें हो जाएं, लेकिन ये ग्लोरिफाई हों। यह कहा जाए कि दिया तमाचा, दिया तमाचा, दिया थप्पड़, यह कैसे चलेगा, इसमें कौन बचेगा? जिस दिन हम राजनीतिक लोगों की जमात अलग हो जाएगी, मैं आपको कहता हूं कि समाज का कोई हिस्सा नहीं बचेगा। इसलिए मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं और इस सारी बात के लिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मर्यादायें बांधने के बगैर लोकतंत्र नहीं बचेगा। यही मुझे कहना है, धन्यवाद।

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): I associate with the strong sentiments expressed by the Leader of the House, the Leader of the Opposition, and Shri Sharad *ji*. I condemn the incident that had taken place yesterday. People have the right to protest and resort to agitation against the policies of the Government.

But they should not take up violent methods. This is dangerous for democratic institution and for democracy of our country as a whole. I feel that what happened yesterday is an insult to democracy. The person who attacked Shri Sharad Pawar, a senior Member, a Minister and a senior politician may be insane, but it is a condemnable act. So, the House has condemned it and the hon. Speaker also made a Reference condemning the incident. We also strongly condemn what happened yesterday.

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): सभापति जी, अभी प्रणब दादा, नेता प्रतिपक्ष तथा शरद जी और सीपीएम के बस्देव आचार्य जी ने जो सेन्टिमन्ट रखा है उससे मैं अपने को संबद्ध करता हूं। मान्यवर, शरद पवार जी का 45 साल का राजनैतिक जीवन रहा है। वह महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर रहे हैं। वह दिल्ली में एक लंबे अर्से से मिनिस्टर के विभिन्न पदों पर आसीन रहे हैं। अभी वह कृषि मंत्री हैं। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसमें मैंने कल देखा, बिना नाम लिए मैं कहना चाहूंगा कि एक आदमी ने कहा कि केवल एक ही थप्पड़ मारा।...(व्यवधान) मान्यवर, मैं समाज के लोगों से यह कहना चाहता हूं कि जैसा शरद जी ने कहा कि आज ज्यादातर लोग जो यहां बैठे हैं, वे अपना खून-पसीना बहा कर और जनता का विश्वास हासिल कर यहां आए हैं। जिस तरह से उनको डाउनग्रेड किया जा रहा है, जिस तरह से पार्लियामेंट की मानहानि की जा रही है, इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि अगर यह संस्था खत्म हो गई तो देश में कोई संस्था नहीं बचेगी। मुझे याद है कि महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन छेड़ा था उस आंदोलन में अहिंसा ही उनका सबसे बड़ा अस्त्र था। इतने बड़े ब्रिटिश एम्पायर को उन्होंने अहिंसा के बल पर ध्वस्त कर दिया। लेकिन इस तरह की घटना, मान्यवर वह पहले भी दो बार दूसरे लोगों पर हमला कर चुका है। मुझे ताज्जुब है कि उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर यही सिलसिला चलता रहा तो इसका कहीं अंत नहीं होने वाला है। मैं आप से आग्रह करूंगा कि हाउस के सेन्टिमन्ट को देखते हुए सरकार से यह कहें कि सरकार भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न होने दे। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY): Mr. Chairman, Sir, we strongly condemn the attack on Shri Sharad Pawar which happened yesterday. Our leader, the Chief Minister of West Bengal, Kumari Mamata Banerjee was addressing a meeting of industrialists in Delhi yesterday. It was an interaction

session where the media persons also asked her a question. She immediately stopped her interaction and condemned this incident in the presence of the national media. She stated that we can never tolerate such type of incidents.

Sharad Pawarji is, no doubt, a reputed leader of national stature. The Government should not keep silent on such type of heinous attacks and exemplary punishment should be meted out to such persons so that nobody has the courage to attempt such a thing in future. We hope that the unanimous decision of the House will send a strong message and signal to such sections who are already isolated from the society.

But this message will certainly help us to restrain from such types of incidents so that these incidents will never happen in future.

श्री धनंजय सिंह (जीनपुर): सभापित महोदय, नेता सदन इस सदन में जो निन्दा प्रस्ताव लाए हैं, मैं निश्चित रूप से उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं उम्मीद कर रहा था कि ग्यारह बजे यह प्रस्ताव आ जाएगा। जिस तरह नेता प्रतिपक्ष, शरद जी, रेवती रमण सिंह जी और बाकी सदस्यों ने इसकी निन्दा की है, मैं भी अपने की तरफ से इसकी घोर निन्दा करता हूं। मैं यहां एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस देश में पिछल एक वर्ष से जो वातावरण बना है, जिस तरह सामाजिक वातावरण खराब करने का माहौल बना है, रेवती रमण जी ने उस पर थोड़ा प्रकाश डालने का काम किया है। हम राजनीतिज्ञों पर एक डिसबिलीफ की बात की गई। मैं कल मीडिया की खबर देख रहा था, शरद जी ने मीडिया की तरफ प्रकाश डाला था, मीडिया कह रही थी कि यह कहीं राजनीतिज्ञों के ऊपर अविश्वास की परिणित तो नहीं है। इंडिया टीवी या किसी और न्यूज़ चैनल में खबर चल रही थी। क्या हम इतने अविश्वसनीय हो गए हैं? पिछले एक वर्ष में जिस तरह का वातावरण बना है, हमने एकजुट होकर उसका सामना करने में कहीं न कहीं अपने आपको अक्षम पाया है।...(व्यवधान)

सभापित महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है। माननीय शरद पवार जी को 45 वर्षों का राजनीतिक अनुभव प्राप्त है। वे कभी कोई चुनाव नहीं हारे। वे 45 वर्षों से लगातार विधान सभा और लोक सभा के सदस्य के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। वे बहुत सरल और सहज व्यक्ति हैं। मेरा भी उनसे काफी इंटरएक्शन रहा है, इसलिए मुझे बेहद पीड़ा हुई है। वे बहुत सरल और सहज हैं और कोई सिक्युरिटी लेकर नहीं चलते। अगर उनके पास कोई भी सांसद किसी भी कार्य के लिए जाता है, तो वे उसे हमेशा करने के लिए तैयार रहते हैं। वे आम आदमी से मिलने के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं। उनको राजनीतिक जीवन

का बहुत लम्बा अनुभव प्राप्त है। यह हम लोगों के लिए निश्चित रूप से पीड़ादायी विषय है। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। देश गवाह है कि ऐसी घटनाओं के रिटैलिएशन भी होते हैं। मान लीजिए इस घटना का रिटैलिएशन होता तो उसका सामना कौन करता? हमारे जो भी सीनियर लीडर्स हैं, चाहे किसी भी दल के हों, हम दल से अलग जाकर बात करते हैं, वे देश की धरोहर हैं, उनके विचार देश की धरोहर हैं। ऐसे लोगों की सुरक्षा करना सदन और सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हम ध्यान दें कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न होने पाए। इसकी जितनी निन्दा की जाए, उतनी कम है। मैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से इसकी निन्दा करता हूं।

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): सभापति जी, यहां माननीय स्पीकर महोदया के माध्यम से जो प्रस्ताव रखा गया, उस बारे में माननीय प्रणब दादा, सुषमा जी और अन्य नेताओं ने इस विचार के साथ अपने आपको जोड़ा। शरद पवार जी मेरे नेता हैं, इसलिए मैं यहां नहीं खड़ा हुआ हूं। वे निश्चित ही इस देश के एक महत्वपूर्ण नेता हैं जिनका सार्वजनिक जीवन में बह्त लम्बा और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कल की घटना के बारे में जैसे बाकी नेताओं ने कहा, निश्चित ही लोकतंत्र के भविष्य के ऊपर बहुत बड़ा सवाल पैदा करती है। अगर हम सब लोगों ने मिलकर इस प्रकार की घटनाओं को रोकने का काम नहीं किया, इसकी निन्दा नहीं की, तो निश्चित ही हमारी संस्थाओं में निरंतर गिरावट होती जाएगी। वैसे भी सार्वजनिक जीवन में, जैसे शरद जी ने कहा, राजनेताओं के मामले में हर आदमी प्रश्न लगाने के लिए तत्पर हो जाता है। न जाने क्यों एक ऐसा वातावरण बन गया है कि जो भी व्यक्ति सार्वजिनक या राजनीतिक जीवन में काम करता है, वह गलत होगा या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ही काम करता है। एक प्रकार से आम माहौल बन गया है। लेकिन यह सब होने के बावजूद भी हम सब लोगों ने यहां एकता का जो स्वरूप प्रकट किया, उसके लिए मैं आप सब नेताओं का धन्यवाद करता हूं। केवल इतना ही कहूंगा कि कल की घटना के पश्चात स्वाभाविक है कि कुछ लोगों के मन में एक उत्तेजित भावना पैदा हुई हो। महाराष्ट्र में, विशेषकर जहां शरद पवार जी का लम्बा सार्वजनिक जीवन बीता है, वहां लोगों ने कुछ घटनाओं के मामलों को लेकर अपने आप रीएक्शन देने का काम किया। लेकिन शरद पवार जी ने तुरंत एक सुलझे हुए नेता के नाते सभी लोगों से अपील की। हम सब लोगों को उन्होंने फोन करके कहा कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। ऐसा कई बार हो जाता है। जीवन में इस प्रकार की बातें कम ज्यादा होती हैं। सार्वजनिक जीवन में कई उतार-चढाव हम सब देखते हैं, लेकिन उन्होंने एक सुलझे हुए एक नेता के तौर पर इस पूरी घटना को बड़े साधारण तरीके से लिया और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना महाराष्ट्र या अन्य किसी भी जगह नहीं होने दी। इसीलिए मैं यहां पर इतना ही कहूंगा कि हम

सब लोगों को देखना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी घटना किसी भी राजनेता पर न हो और इस मामले में जो गुनाहगार लोग हैं, उन पर सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): Mr. Chairman, Sir, please permit me to speak from this place.

MR. CHAIRMAN: Okay.

SHRI T.K.S. ELANGOVAN: Mr. Chairman, Sir, on behalf of the DMK, I condemn the incident happened yesterday against one of the very senior leaders of Indian politics.

There are established democratic systems through which anybody can raise his or her opposition against the Government or against a Minister. I fully agree with hon. Sharad Yadav *ji* that the role of media is very important in such things. I only request the media not to project this pseudo heroism, otherwise this will crop up everywhere in other parts of the country. So it is the role of the media to see that such pseudo-heroism, such anti-national activities, such anti-establishment activities should not be encouraged by the media.

With these words, I condemn the incident which took place yesterday. SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Mr. Chairman, Sir. I stand here on behalf of Biju Janata Dal to condemn the atrocious attempt that was imparted in a public function to a national leader Sharad Pawar *ji*. I stand here also to condemn the action of the person; I do not condemn the person. The action should be condemned and action should also be taken by the Government that such type of action is not repeated on any other person at all. Actions are to be condemned which are deprecating, which are condemnable. I would again request the Government to find out whether there was a lack of security.

We all know Sharad Pawar *ji* always moves without security. But, with the change of situation that is prevalent in this country today, there are one or two circles of security in a different method. Was there a breach of security? That has to be probed and accordingly action should be taken.

I join all my leaders, all my colleagues in this House in condemning the atrocious action that happened yesterday.

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): सभापित जी, कृषि मंत्री और राष्ट्र के नेता शरद पवार जी के साथ कल जो घटना घटी, उसकी मैं शिवसेना की ओर से निंदा करता हूं। हमने तुरंत ही इस घटना की निंदा की है। हमने स्पीकर महोदया को एक चिट्ठी भी लिखी थी कि इस सदन की ओर से इस प्रकार की घटना की भर्त्सना करनी चाहिए, उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। आज स्पीकर महोदया ने यहां पर उसकी कड़ी निंदा की है। एक अच्छी बात है कि सदन के नेता, विपक्ष के नेता और पूरे सदन की ओर से, जो हमला कल शरद पवार जी पर हुआ, उसकी कड़ी निंदा इस सदन में हो रही है। एक आशंका मन में आती है कि जिस प्रकार से ये सारी घटनाएं कई दिनों से हो रही हैं, इससे जो देश के राजनेता हैं, उन्हें नीचे गिराने का प्रयास लगातार चल रहा है। यह एक तरह से हमारे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। जब भी इस प्रकार की बातें आती हैं, तो हम अपने सारे विवादों को छोड़कर इस सदन और लोकतंत्र की गरिमा को बनाये रखने का प्रयास करते हैं और इसी में आज की यह पहल है।

हम इस घटना की निन्दा तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ-साथ जिस अपराधी ने यह घटना की है, हमला किया है, उसे भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यह कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए कि दूसरों को इससे सबक मिले और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। मै शिवसेना की ओर से इस हमले की कड़ी निन्दा करता हूं।

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Mr. Chairmenowadays, democracy is being challenged by such type of incidents. Violence is not solution to solve any problem. To create fear and destabilise the country, some unscrupulous elements are doing such type of acts.

So, on behalf of AIADMK, we strongly condemn the incident which took place yesterday. The hon. Minister of Agriculture, Shri Sharad Pawar is a decent and senior most politician. So, on behalf of my Party, I also join with my colleagues to condemn this incident.

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Sir, I unequivocally condemn the incident. Why do we condemn it? I know Shri Sharad Pawar for a quite long time. He is a very senior politician. He is a senior Minister. But that is not the issue. This is not the way to protest. The man, who attacked him, has spoken to the

Press that he is protesting against price rise and unemployment. We must make it clear as a political activist that in a democratic set-up every single person or a Party has a right to protest against the Government policy but there is a way to protest. Slapping a Minister to protest against the Government policy in the open is not acceptable in a democratic society as a method of protest. That is the main issue. It is not whether he is a good man or not. He is, of course, a good man or not. It is not the issue whether he is a senior politician. Yes, he is a senior politician. Does it mean a junior politician can be slapped? Does it mean that the Minister of State can be slapped? Seniority is not the question. His place in the society is not the question.

The question is this. This Parliament must condemn this method of protest. This method of protest is unacceptable in the society. Individual vandalism is unacceptable. We have a protest. We can go on strike; we can organize a demonstration; we can raise it in Parliament. Whatever way we can do we can protest and we have a right to protest but this is the most heinous way which weakens the protest. Individual vandalism weakens the protest. Therefore, I condemn it. This is not the way to protest. Whatever indignation that man, if he is a senile man or a sensible man might be having, this is not the way to protest.

I put on record one thing. Mr. Anna Hazare did a very wrong thing. I do not know what is happening. And secondly, I do not appreciate the electronic media, constantly showing the picture as to how he has been slapped. Is it the way? Media is sensationalizing a barbaric incident. Is it the way? The Press must have a lesson. In a democracy, in a decent society, in a civilized society, let us not over-publicise an incident, which is to be condemnable, however popularity a particular media may get. That is not the issue. These two points are also to be taken note of by this august House.

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): Sir, yesterday the incident that took place was outside the premises of Parliament when the Minister was going out. I do not know whether it is a civil society provocation or provocation by any quarter.

This is one of the heinous crimes that everyone has to condemn. This is unpardonable. I also came to know that in the past, Shri Sukh Ram, one of the former Ministers, had also faced the same type of attack. I am not going to justify the role of the Ministers in a corruption matter or any other matter but the law has to take its own course.

Leaving the person free after the incident on Shri Sukh Ram gave a sort of shelter or protection to him to go and attack further.

It is not only the question of giving protection to the Members of Parliament but also it is the question of giving protection to the citizens of this country. The Speaker can give protection to the Members of Parliament within the ambit of the House but outside the House we are normal citizens, and protection cannot be given in every place where we are going on tour.

This type of incident must be dealt with very severely. Judiciary must also take note of such incidents and these persons should not be let loose.

I am so sorry about how things have happened in the past. There is no question of showing any mercy on such persons. I am not bothered whether the person is sane or insane. Severe punishment must be given to him. The way in which he dragged his knife, which I saw on TV – my friend has said how the electronic media was repeatedly showing that incident – shows his intention to murder.

It is not the question of price rise alone but his intention was to murder Shri Sharad Pawar, who is not only a senior Minister but also one of the most respected persons. I got tears in my eyes yesterday when I saw it and I wrote him a letter. I am so sad about the whole incident.

Today morning, the hon. Speaker, on behalf of the entire House, made a Reference to condemn this incident. At that time we wanted to speak but all other issues came together and the House was adjourned.

Sir, I join all my colleagues to condemn this incident and it should not be allowed to take place whether in the premises of Parliament or outside in future. So, protection must be given to the Members. This is all I want to say.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI E. AHAMED): Sir, I wish to express my sentiments against the act of violence shown to a very seasoned politician of this country.

On behalf of my Party, Indian Union Muslim League, I associate myself with the sentiments expressed by the Leader of the House and other leaders in this House.

I would just like to say that the views expressed by Shri Sharad Yadav ji and Shri Gurudas Dasgupta ji in this House are totally acceptable to all the political activists, to all the political parties and to all those who believe in democracy.

There is no place for violence in politics. Irrespective of our philosophy, our parties, our politics and our aims, if we will not be able to condemn such heinous acts of violence, India's future will be very bleak. Therefore, unanimously all of us have to accept the sentiments expressed by this House. My party very severely condemns this act and we wish that Sharad Pawarji who has been serving the country all these years will continue to serve this country with more vigour and more courage.

श्री जयंत चौधरी (मथुरा): सभापित जी, अभी नेता सदन ने और सभी राजनैतिक दलों ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। मैं यहां सभी सांसदों और दलों की ओर से व्यक्त भावनाओं से अपने आपको सम्बद्ध करता हं।

हमारा देश विविधताओं का देश है। हो सकता है कि हमारी राय अलग हो, विचार भिन्न हों और यह भी हो सकता है कि जिस आदमी ने यह कार्य किया, वह मानसिक रूप से असंतुलित हो, लेकिन हरेक नागरिक को यह पता होना चाहिए कि अगर वह कानून को अपने हाथ में लेता है तो वह अपने समाज और देश की परम्पराओं से अलग खड़ा है। मीडिया में चर्चा हुई है और मैंने भी एक इंग्लिश मीडिया चैनल में

देखा कि यह टिप्पणी हुई कि "Angry youngman protesting against price-rise". यह प्रोटेस्ट का कोई फॉर्म नहीं हो सकता है। मैं इस घटना की निंदा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं यहां खड़ा हूं इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि इस वक्त समाज का हरेक वर्ग आगे बढ़कर इस बात को स्वीकार करेगा कि यह जो घटना और तरीका है, यह लोकतांत्रिक नहीं है और इसे हम अपनी राय नहीं मानते। मैं इस विश्वास के साथ खड़ा हुआ हूं कि समाज का हरेक वर्ग संयम से काम ले और स्वीकारे कि दुनिया में हमारा देश अहिंसावादी और टॉलरेंस समाज के रूप में माना जाता है। हम शांतिप्रिय लोग हैं, अगर यहां कोई ऐसी घटना होती है तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापित महोदय, कल जो अमर्यादित घटना हुई और माननीय शरद पवार जी पर हमला हुआ, सदन के अंदर और बाहर सभी दलों के नेताओं और लोगों ने उसकी निंदा की है, मैं भी इस आचरण की घोर भर्त्सना करता हूं।

महोदय, मुझे जानकारी मिली कि पहले भी उसने किसी पर हमला किया है, या तो वह सिरिफरा है, पागल है या वो छपास-छुपास वाले लोग होते हैं, वे भी इस तरह से कार्य करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पहले उसने किसी पर हमला किया और फिर वैसा ही कार्य किया, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मुझे लगता है कि कहीं ढिलाई हुई है। सभी लोग स्वीकार करते हैं कि देश में लोकतंत्र है और किसी को अमर्यादित आचरण की इजाजत नहीं दी जा सकती है। जिसका दिमाग सही होगा, वह इस तरह की कार्रवाई की निंदा ही करेगा और इसे सहन नहीं करेगा। उसने पहले हमला किया और फिर दुबारा हमला किया। अब माननीय शरद पवार जी तो बड़े नेता हैं, बड़े आदमी हैं, उन पर हमला होने से जरूर जहां-तहां उत्तेजना फैलेगी, लेकिन हम उनके समर्थकों और नेताओं का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने शांति बनाए रखने का प्रयत्न किया। लेकिन किसी भी साधारण आदमी पर भी हमले की इजाजत लोकतंत्र में नहीं दी जा सकती है। इसलिए सभापति जी, कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इस बात की जांच होनी चाहिए। क्या वह पागल है, सिरफिरा है, क्या स्थिति है? पागल को तो बंद करके रखा जाता है, नहीं तो वह दूसरे-तीसरे व्यक्ति को मारेगा। मीडिया के माध्यम से पता लगा कि उसने पहले भी किसी पर हमला किया है तो अभी तक वह बाहर कैसे रहा, इस बात की जांच होनी चाहिए और आगे इस तरह की और कोई घटना न हो, इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। प्रतिवाद करने की हमेशा गुंजाइश होती है लेकिन इस तरह का अमर्यादित आचरण और हिंसा कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई पसंद नहीं करेगा। लेकिन कुछ राजनीति भी इसमें जहां-तहां है, प्राइस-राइज, प्राइस-राइज। देश में अनेकों समस्याएं हैं और विभिन्न पार्टियों के बीच में अनेकों मतभेद हैं लेकिन मारापीटी हो, अमर्यादित आचरण हो, गाली-गलौज हो, इसकी सदन या

बाहर, कहीं भी गुंजाइश नहीं है। इसलिए इसकी सब तरफ से निंदा की जानी चाहिए और सदन एकजुट होकर इस पर निंदा प्रस्ताव पास करे।

SHRI K. CHANDRASEKHAR RAO (MAHBUBNAGAR): Mr. Chairman, Sir, I associate myself with the sentiments expressed by the hon. Leader of the House, the hon. Leader of the Opposition and other leaders of the House.

The incident, which has happened to Sharad Pawar Ji needs to be strongly condemned. This kind of mindless, meaningless violence and physical attack needs to be reviewed by the Government and the Government should take steps to see that this kind of incidents should not take place in future.

With this, I strongly condemn this worst incident.

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I associate myself with the feelings of anger that have been expressed in the august House.

I also like to say one point over here, which is that a thorough inquiry should be ordered because yesterday's function was not a huge function. An inquiry should be ordered. The phone record of that person should be checked as to how come that man was there at that particular point of time because there must be some connection whatsoever. Because, unless and until someone tells that person that here you have a Union Minister coming over here, how did that man appear over there? It was an NDMC function. I could understand if it was a function of his Ministry. So, a thorough inquiry should be ordered.

And, this is also a point wherein a debate should take place in the country that how come a convicted person in a court, who attacks, gets bail and what kind of bail laws are existing in this country. They give bail to a person who attacks in the court and then there are other issues also, which I do not want to put over here. But now what will happen? With this, the same court will give him bail again. So, there should be a debate on bail laws in this country if someone attacks anyone, especially in the court. Now, the attack is on the Minister. So, we would like to know what will be the role of the hon. judiciary now. How quickly are they going to give bail to this particular person?

MR. CHAIRMAN: Now, you please conclude.

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): So, I strongly condemn this act. A thorough inquiry should be ordered. My heart goes out to my colleague, Shrimati Supriya Sule also. I am really thankful to the NCP cadres for showing restraint and maintaining peace. Thank you.

श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका): सभापित महोदय, मैं अपने पूर्वक्ता साथियों के विचारों और भावनाओं से पूरी तरह से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए कल श्री शरद पवार पर हुए हमले की घोर भर्त्सना करती हूं। मेरा मानना है कि लोकतांत्रिक समाज में हम इस तरह की घटना को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह बात सच है कि हम आज भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों पर लड़ रहे हैं, लेकिन विरोध जताने का यह तरीका हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।

मैं एनसीपी के सदस्यों को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने शांति को बनाए रखा। मैं प्रमुख गांधीवादी नेता द्वारा दिए गए बयान की भी निंदा करती हूं, जो उन्होंने कहा कि " सिर्फ एक थप्पड़ "। मुझे मीडिया बंधुओं पर भी आश्चर्य है, क्योंकि उन्होंने इस घटना को टीआरपी बनाने के चक्कर में बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और ग्लोरीफाई करने की कोशिश की। मैं इसकी घोर निंदा करती हूं।

SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): On behalf of my Party, RSP, I condemn this incident. But why this incident happened? I think it has happened due to the protest on price rise. Everyone has his right to protest but not in this manner in a democracy. So, everyone of this country should condemn it and the person, who had done this, should be punished.

SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Sir, today the sad issue, which we are discussing, should be condemned.

It should be thoroughly investigated as to how this incident took place. We have difference in ideologies in this House about matters like price rise and all other things. But, such a behaviour and incidents should not take place. So, I condemn it strongly and it should be thoroughly investigated how it has happened. ... (*Interruptions*)

 \blacksquare

12.45 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Now, Papers to be laid on the Table. Shri S.S. Palanimanickam.

12.46 hrs

At this stage, Shri K. Chandrasekhar Rao and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following Notification (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873:-
 - (i) The Senior Citizens Savings Scheme (Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 770(E) in Gazette of India dated 19th October, 2011.
 - (ii) The Post Office Savings Account (Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 681(E) in Gazette of India dated 15th September, 2011.
 - (iii) The Post Office Recurring Deposit (Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 740(E) in Gazette of India dated 4th October, 2011.
 - (iv) The Post Office (Monthly Income Account) Amendment Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 741(E) in Gazette of India dated 4th October, 2011.

(v) The Post Office Time Deposit (Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 742(E) in Gazette of India dated 4th October, 2011

(Placed in Library, See No. LT 5301/15/11)

- (2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959:-
 - (i) The Kisan Vikas Patra (Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 743(E) in Gazette of India dated 4th October, 2011.
 - (ii) The National Savings Certificates (VIII Issue) Amendment Rules,
 2011 published in Notification No. G.S.R. 744(E) in Gazette of India dated 4th October, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 5302/15/11)

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Food Safety and Standards Authority of India, New Delhi, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Food Safety and Standards Authority of India, New Delhi, for the year 2009-2010.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 5303/15/11)

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 93 of the Food Safety and Standards Act, 2006:-

(i) The Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 published in Notification F. No. 2-15015/30/2010 in Gazette of India dated 1st August, 2011.

- (ii) The Food Safety and Standards (Laboratory and Sample Analysis)
 Regulations, 2011 published in Notification F. No. 2-15015/30/2010
 in Gazette of India dated 1st August, 2011.
- (iii) The Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulations, 2011 published in Notification F. No. 2-15015/30/2010 in Gazette of India dated 1st August, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 5304/15/11)

(4) A copy of the Notification No. F. No. P-15025/41/2011-DFQC (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 4th August, 2011 repealing the enactments and orders in the Second Schedule of the Food Safety and Standards Act, 2006 and the Milk and Milk Products Regulations, 1992, with effect from 5th August, 2011, issued under Section 97 of the Food Safety and Standards Act, 2006.

(Placed in Library, See No. LT 5305/15/11)

(5) A copy of the Notification No. G.S.R. 752(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 12th October, 2011 prohibiting the drug Letrozole for induction of ovulation in an ovulatory infertility, issued under Section 26A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940.

(Placed in Library, See No. LT 5306/15/11)

12.46 hrs.

ELECTION TO COMMITTEE

Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Schedule Tribes

MR. CHAIRMAN: Shri Gobinda Chandra Naskar – not present.

Shri Mohinder Singh Kaypee.

SHRI MOHINDER SINGH KAYPEE (JALANDHAR): I beg to move:

"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate one member from Rajya Sabha to associate with the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Schedule Tribes for the unexpired portion of the term of the Committee *vice* Shri Silvius Condpan died and do communicate to this House the name of the member so nominated by Rajya Sabha."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate one member from Rajya Sabha to associate with the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Schedule Tribes for the unexpired portion of the term of the Committee *vice* Shri Silvius Condpan died and do communicate to this House the name of the member so nominated by Rajya Sabha."

The motion was adopted.
... (Interruptions)

12.46 ½ hrs.

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) First meeting of Prime Minister's Committee on National e- Governance Plan (NEGP) held on 23.11.11*

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI KAPIL SIBAL): I beg to lay the statement regarding the first meeting of Prime Minister's Committee on National e-Governance Plan (NeGP) held on November 23, 2011.

I am happy to inform you that the first meeting of the Prime Minister's Committee on National e-Governance Plan (NeGP) was held on 23.11.2011.

Under National e-Governance Plan, initiatives like Income Tax, MCA 21, Passports, Central Excise have started delivering online services to the citizens. It is the endeavour of the Government to expand the number of public services that are available to citizens in electronic mode. Accordingly, the Committee emphasized the urgent need for adoption of e-Governance in all walks of Governance to enhance accountability, transparency and efficiency and to realize the objective of inclusive growth with equity.

The PM's Committee also decided to introduce the Electronic Delivery of Services (EDS) Bill in the winter session of the Parliament to mandate e-Delivery of all Public Services within 5 years of the commencement of the Act in all Ministries of the Central Government.

To give further impetus to e-Governance it has also been decided to constitute an Expert Group to review each Mission Mode Project and suggest measures to address critical issues including process re-engineering, augmentation of project teams where needed, standards, creation of common platforms and integration across projects.

_

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 5307/15/11.

The high growth rate of our economy has resulted in a significant increase in the Government procurements and it is the policy of the Government to ensure the highest degree of transparency and accountability in Public Procurement. Accordingly, it has been decided that e-Procurement will be adopted mandatorily in a phased and time-bound manner. The Department of Expenditure will drive the adoption of e-Procurement by Central Ministries/ Departments, Central Public Sector Enterprises (CPSEs) and Autonomous/ Statutory bodies and the e-Solutions would be certified by DIT on technology and security.

The Government has also decided to initiate new e-Governance projects for Education, Health, Public Distribution System and Postal Services. This would ensure access to quality education, cost efficient and quality health care and postal services to the common man at an affordable cost. The initiatives for PDS will help bringing in transparency and efficiency and also eliminate corruption.

In order to leverage the rapid growth in penetration of mobile technology and connectivity the PM's Committee on NeGP decided that public services under all e-Governance projects will be delivered through Mobile Devices like Mobile phones and Aakash Tablets also to ensure reach and accessibility of all services to the common man.

Further basic Banking Services i.e. cash withdrawal, cash deposit, balance inquiry and transfer of money from one account to another will be extended to every Panchayat through CSCs and money transfer facility will be extended to every Village by December, 2013 leveraging ICT and Mobile technology. This will ensure that Financial Inclusion becomes a reality.

These initiatives will have a significant impact on improving Governance and reducing corruption and hardships that the citizens have to face in accessing public services and will go a long way in ensuring Inclusive Growth with equity and transparency.

12.46 ½ hrs.

(ii) (a) Decision of Union Cabinet on the Revival Reform and Restructuring package for handloom sector*

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY AND MINISTER OF TEXTILES (SHRI ANAND SHARMA): I beg to lay the statement regarding the decision of the Union Cabinet on the Revival Reform and Restructuring Package for handloom sector.

In the Budget speech for 2011-12 on 28.2.2011, the Finance Minister had announced that the Government of India would provide Rs.3000 crore for implementing the financial package for handloom sector for waiver of overdue loans. As a follow up of the Budget announcement, the Government has now approved the following:

(i) To implement the "Revival, Reform and Restructuring Package for Handloom Sector" starting with the current financial year as a new Centrally Sponsored Plan Scheme with a total outlay of Rs.3884 crore. The component-wise details of the Financial Package are as follows:

S.No.	Component	Rs. crore
1.	1. Loan waiver and recapitalization of handloom weaver	
	cooperative societies as on 31.03.2010.	
2.	Waiver of individual weaver loans as on 31.3.2010	500
3.	Strengthening of weaver cooperative societies	88
4.	3% Interest Subsidy for fresh loans	180
5.	Credit Guarantee for fresh loans	25
6.	Training for the functionaries	30
7.	Loss assessment exercise & Cost of Implementation	40
	Total	3884

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 5309/15/11.

(ii) Out of the total amount of Rs. 3884 crore, the share of the Government of India will be Rs. 3137 crore and that of the State Governments will be Rs.747 crore.

(iii) The funds required for loan waiver and recapitalization of handloom weavers cooperative societies and that for individual weavers (Sl.No.1 and 2 respectively in the table above) will be shared in the following ratio between the Government of India and States concerned:

S.	Beneficiary	General Category	Special Category
No.		States (Centre : States)	States (Centre : States)
(i)	State level apex societies	75:25	90 : 10
(ii)	Primary handloom	80:20	90 : 10
	cooperative societies		
(iii)	Individual weavers/SHGs	80:20	90:10
	etc.		

- (iv) Under the scheme, funds will be provided for repayment of 100% of principal and 25% of interest, which is overdue as on 31.03.2010 in respect of viable and potentially viable Primary Weavers Cooperative Societies and Apex Societies as well as in respect of individual handloom weavers, master weavers, Self Help Groups and Joint Liability Groups who have taken such loans for handloom weaving purposes, provided the banks agree for sanctioning fresh loans. There would be an overall ceiling of Rs.50,000 per individual beneficiary as far as funding under this scheme is concerned in respect of waiver of overdues of individual handloom weavers.
- (v) The Government has further approved an interest subvention of 3% for 3 years to be extended from the date of disbursal of the fresh loan extended by banks to the eligible handloom cooperative societies and individual handloom weavers

covered under this Scheme. The interest subvention would not be made available from the date on which a loan becomes non-performing asset.

- (vi) The Government will make necessary provision for credit guarantee for a period of three years for the fresh loans extended as per para (v) above.
- (vii) The Government has further approved the constitution of three levels of Committees at the national, state and district levels for implementing and monitoring the scheme.
- (viii) The Government has also approved the releasing of 80% of the share of Government of India on signing of MoU with the State Governments and NABARD, and on completion of loss assessment exercise in a particular State.

12.46 3/4 hrs.

(ii)(b)Policy on Foreign Direct Investment for allowing FDI in Multi-Brand Retail Trading and Liberalization of the policy in Single Brand Tetail Trading *

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY AND MINISTER OF TEXTILES (SHRI ANAND SHARMA): I beg to lay the statement regarding the policy on Foreign Direct Investment for allowing FDI in Multi-Brand Retail Trading and liberalization of the policy in Single-Brand Retail Trading.

The Government has approved the proposal of the Department of Industrial Policy & Promotion for allowing FDI in Multi-Brand Retail Trading and liberalization of the policy in Single-Brand Retail Trading. The details of the proposals approved are as under:

(1) FDI in Multi-Brand Retail Trading:

- (i) FDI in Multi Brand Retail Trade may be permitted up to 51%, with Government approval;
- (ii) Fresh agricultural produce, including fruits, vegetables, flowers, grains, pulses, fresh poultry, fishery and meat products, may be unbranded.
- (iii) Minimum amount to be brought in, as FDI, by the foreign investor, would be US \$ 100 million.
- (iv) At least 50% of total FDI brought in shall be invested in 'back-end infrastructure', where 'back-end infrastructure' will include capital expenditure on all activities, excluding that on front-end units; for instance, back-end infrastructure will include investment made towards processing, manufacturing, distribution, design improvement, quality control, packaging, logistics, storage, ware-house, agriculture market produce infrastructure etc. Expenditure on land cost and rentals, if any, will not be counted for purposes of backend infrastructure.

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 5310/15/11.

(v) At least 30% of the procurement of manufactured/ processed products shall be sourced from 'small industries' which have a total investment in plant & machinery not exceeding US \$ 1.00 million. This valuation refers to the value at the time of installation, without providing for depreciation. Further, if at any point in time, this valuation is exceeded, the industry shall not qualify as a 'small industry' for this purpose.

- (vi) Self-certification by the company, to ensure compliance of the condition at serial nos. (iii), (iv) and (v) above, which could be cross-checked as and when required. Accordingly, the investors to maintain accounts, duly certified by statutory auditors.
- (vii) Retail sales locations may be set up only in cities with a population of more than 10 lakh as per 2011 Census and may also cover an area of 10 kms around the municipal/urban agglomeration limits of such cities; retail locations will be restricted to conforming areas as per the Master/Zonal Plans of the concerned cities and provision will be made for requisite facilities such as transport connectivity and parking;
- (viii) Government will have the first right to procurement of agricultural products;

(2) FDI in Single-Brand Retail Trading:

- (i) FDI in single brand retail trading may be permitted up to 100% with Government approval;
- (ii) Products to be sold should be of a 'Single Brand' only.
- (iii) Products should be sold under the same brand internationally i.e. products should be sold under the same brand in one or more countries other than India.
- (iv) 'Single Brand' product-retailing would cover only products which are branded during manufacturing.
- (v) The foreign investor should be the owner of the brand.
- (vi) In respect of proposals involving FDI beyond 51%, 30% sourcing would mandatorily have to be done from SMEs/ village and cottage industries artisans and craftsmen. 'Small industries' would be defined as industries which have a total

investment in plant & machinery not exceeding US \$ 1.00 million. This valuation refers to the value at the time of installation, without providing for depreciation. Further, if at any point in time, this valuation is exceeded, the industry shall not qualify as a 'small industry' for this purpose. The compliance of this condition will be ensured through self-certification by the company, which could be subsequently checked, by statutory auditors, from the duly certified accounts, which the investors will be required to maintain.

12.47 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE*

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): With your permission, Sir, I beg to lay the Government Business during the week commencing Monday, the 28th of November, 2011, consisting of:-

- 1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order paper.
- 2. Discussion and voting on Second Supplementary Demands for Grants (General) for 2011-12.
- 3. Introduction, consideration and passing of the related Appropriation Bill.
- 4. Consideration and passing of the following Bills: -
- (a) The Constitution (One Hundred and Eleventh Amendment) Bill, 2010.
- (b) The Life Insurance Corporation (Amendment) Bill, 2009.
- (c) The Cable Television Networks (Regulation) Amendment Bill, 2011.
- (d) The Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right to User in Land) Amendment Bill, 2010.
- 5. Consideration and passing of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Bill, 2010, after it is passed by Rajya Sabha.

^{*} Laid on the Table.

12.47¹/₄ hrs.

MOTION RE: THIRTIETH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

MR. CHAIRMAN: Shri Pawan Kumar Bansal.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): I beg to move:

"That this House do agree with the Thirtieth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 24th November, 2011."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That this House do agree with the Thirtieth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 24th November, 2011."

The motion was adopted.

12.47 ½ hrs.

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS –(GENERAL), 2011-2012

MR. CHAIRMAN: Now, Item no.8 – Shri Pranab Mukherjee.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Sir, I beg to present a statement (Hindi and English versions) showing Supplementary Demands for Grants in respect of the Budget (General) for 2011-12.

(Placed in Library, See No. LT 5308/15/11)

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet again on Monday, the 28th November, 2011 at 11 a.m.

12.48 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, November 28, 2011/Agrahayana 7, 1933 (Saka).



